

**उत्तराखण्ड शासन**  
**औद्योगिक विकास अनुभाग-2**  
**संख्या: 14/15/VII-2/378-उद्योग/2007**  
**देहरादून: दिनांक: 22 जनवरी, 2008**

**अधिसूचना**

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-11/औ0वि0/07-उद्योग/2004 तथा शासनादेश संख्या-940/औ0वि0/07-उद्योग/2004-05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांक: 1731/उ0नि0-नि0औ0आ0/2007-08 दिनांक 24, अगस्त, 2007 के संदर्भ में मै0 जे0एम0जे0इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, सदगुरु प्लाजा बिल्डिंग, राजपुर रोड, जाखन, देहरादून को ग्राम शिकारपुर, तहसील रुड़की व ग्राम खेमपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में कय/कय अनुबन्धित कुल 49.20 एकड़ भूमि जिराके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
शिकारपुर	549, 550, 551, 555, 556, 557, 563, 578, 579, 580,	49.20
व खेमपुर	583, 577, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 552,	
तहसील	561, 562, 584, 591, 537, 538, 539, 540, 545, 546,	
रुड़की	131, 134म, 137, 135, 154, 169, 170, 171, 172	

1. तालिका में उल्लिखित भूमि के खसरा संख्या-549, 550, 551, 555, 556, 557, 563, 578, 579, 580, 583, 577, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 552, 561, 584, 591, 546 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-50/2003 सी0ई0 दिनांक 10, जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-D Expansion of existing Industrial Estate के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों (नकारात्मक सूची के क्रियाकलापों को छोड़कर) को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। आस्थान के खसरा संख्या- 537, 538, 539, 540, 545, 546, 131, 134म, 137, 135, 154, 169, 170, 171, 172 भूमि किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित/अधिसूचित नहीं है, जिन पर केवल थरट उद्योगों की स्थापना पर ही विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2- औद्योगिक आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियन्त्रित: GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (1) कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा।

3- इस औद्योगिक आस्थान की 20.66 एकड़ भूमि प्रवर्तक कम्पनी तथा उसकी रिसर्टर कन्सर्न इकाईयों के नाम दर्ज तथा अवशेष भूमि कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियन्त्रित: भूमि

कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा तथा तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत करना होगा।

4- औद्योगिक आस्थान के रख-रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटित इकाइयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के संबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

5- प्रस्तावित कय अनुबन्धित भूमि आवेदक के पक्ष में नियमानुसार कय करने के उपरान्त ही उक्त भूमि निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित मानी जायेगी अर्थात् यदि आवेदक द्वारा कय अनुबन्धित भूमि के लिए कय की अनुमति हेतु आवेदन नहीं दिया गया है, तथा अनुमति नियमतः वांछित है, तो प्रवर्तक शासन से भूमि कय की अनुमति प्राप्त करेगा।

6- आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल प्रावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जहाँ भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

7- निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाइयों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किये जा रहे उद्योगों अथवा प्रतिबन्धित सूची के सम्मिलित उद्योगों की स्थापना नहीं की जायेगी।

8- प्रस्तावित स्थल पर सभी अवस्थापना सुविधाओं, यथा: बिजली, पानी, सड़क, नालियों का निर्माण इत्यादि के विकास का कार्य स्वयं प्रवर्तक द्वारा किया जायेगा।

9- औद्योगिक आस्थान में स्थापित किये जाने वाले सभी आवंटियों से यह अप्रडरटेकिंग ली जायेगी कि आस्थान में स्थापित किये जाने वाली औद्योगिक इकाइयों में 70 प्रतिशत नियमित रोजगार प्रदेश के स्थायी लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed) में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

10- प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय-समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

11- उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो राक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

12- मै0 जे0एम0जे0इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के अन्तर्गत आस्थान में स्थापित होने वाली इकाइयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य सम्पूर्ण सुविधाओं के विकास पर व्यय की जानी वाली सम्पूर्ण धनराशि आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा व्यय की जायेगी। मै0जे0एम0जे0इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 निजी औद्योगिक आस्थान है



तथा प्रस्तावित आस्थान में राज्य सरकार के स्तर से कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

13- निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के कियान्वयन हेतु समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(पी०सी०शर्मा)

प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 4615 (1)/VII-2/378-उद्योग/2007 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति सचिवालय विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग सघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुड़की (हरिद्वार)।
14. मै० जे०एम०जे०इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, सदगुरु प्लाजा बिल्डिंग, राजपुर रोड, जाखन, देहरादून।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय पत्रिहार।

आज्ञा से,

(पी०सी०शर्मा)

प्रमुख सचिव।